भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2314

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

उत्तर प्रदेश के स्नातकों की रोजगार योग्यता

†2314. **एडवोकेट प्रिया सरोज:**

श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत घटती विषयगत विशेषज्ञता ने उत्तर प्रदेश के स्नातकों की रोजगार योग्यता और उच्च शिक्षा की तैयारी को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) संशोधित पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन से पूर्व के तीन वर्षों और बाद के तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक छात्रों की प्लेसमेंट दर और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दर क्या है;

(ग) क्या नियोक्ताओं, पेशेवर निकायों या शैक्षणिक विशेषज्ञों ने स्नातकों के बीच घटती विषयगत प्रवीणता के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार की है जो बहु-विषयक लचीली पाठ्यचर्या संरचनाओं, कौशल के एकीकरण पर बल देती है तथा यह सिफारिश करती है कि शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, पूछताछ-संचालित, खोज-उन्मुख एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाने वाला शिक्षाशास्त्र विकसित होना चाहिए। इसका उद्देश्य छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यवसायों, कलाकारों, शिल्पकारों आदि के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना भी है।

एनईपी 2020 के विजन के अनुरूप, सरकार ने मुख्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र को उन्नत करने के लिए कई पहल की हैं ताकि भविष्य के लिए सुलभ प्रतिभा विकसित की जा सके।

उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम को उन्नत करने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा साइंस (डीएस), मशीन लर्निंग (एमएल), साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा तकनीकी विषयों में अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके उद्योग के विशेषज्ञों के इनपुट के साथ अपने मॉडल पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। एआईसीटीई उद्योग, पेशेवर निकायों, शिक्षाविदों एवं अन्य हितधारकों के साथ नियमित परामर्श भी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी शिक्षा एनईपी के उद्देश्यों के अनुरूप प्रासंगिक, योग्यता-आधारित, बहु-विषयक और विकसित कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप बनी रहे।

एआईसीटीई की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका वर्ष 2024-25 से वर्ष 2026-27 में "तकनीकी संस्थानों के लिए आवश्यक तथा वांछनीय आवश्यकताएं" हैं, जिसमें अनुमोदन के लिए आवश्यक आवश्यकताओं के रूप में संस्थान-उद्योग प्रकोष्ठ, संस्थान की नवाचार परिषद की स्थापना तथा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल हैं।

छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा एनईपी 2020 के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) जारी किया गया है, जो शिक्षा में शिक्षा कौशल के एकीकरण को सक्षम बनाता है। एनसीआरएफ में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक कुल क्रेडिट का अधिकतम 50 प्रतिशत संचयन करने का प्रावधान है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और शिक्षार्थियों के बीच कौशल विकसित करने और उन्हें उद्योग के लिए तैयार करने के लिए " भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए सतत एवं सुदृढ़ विश्वविद्यालय-उद्योग संपर्क प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रोजगार क्षमता में सुधार लाने, अनुसंधान के लिए रुचि विकसित करने तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए एक्सपोजर प्रदान करने के उद्देश्य से "अवर स्नातक छात्रों के लिए इंटर्नशिप/रिसर्च इंटर्नशिप के लिए दिशानिर्देश" भी प्रस्तावित किए हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं का समावेशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अप्रेंटिसशिप-एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) संचालित किए जाने संबंधी यूजीसी दिशानिर्देश” भी तैयार किए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय युवाओं की रोजगारयोग्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उद्योगों के सहयोग से कार्यस्थल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है और फरवरी, 2024 में स्वयम् प्लस मंच का शुभारंभ भी किया गया है। यह मंच रोजगारोन्मुखी 500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। इन पाठ्यक्रमों का चयन 15 क्षेत्रों में कार्यरत 80 से अधिक औद्योगिक भागीदारों के सहयोग से किया गया है, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, बीएफएसआई,

स्वास्थ्य सेवा तथा उन्नत विनिर्माण आदि क्षेत्र शामिल हैं। कौशल संवर्धन हेतु स्वयम प्लस मंच पर 06 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने नामांकन कराया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) का कार्यान्वयन किया गया है। एनएमईआईसीटी के अंतर्गत, समर्थ नामक एक उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) सॉफ्टवेयर मंच प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) की प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा शासन-संबंधी प्रक्रियाओं का प्रारंभ से अंत तक डिजिटल रूपांतरण सुनिश्चित करना है। इस मंच का अभिप्राय कार्यप्रणालियों को सुव्यवस्थित बनाना, कागजी कार्यवाही में कमी लाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करना है।समर्थ में प्रवेश, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सहित 40 से अधिक मॉड्यूल उपलब्ध हैं।

समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 17 लाख से अधिक छात्रों ने स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिला लिया है, जिन्होंने समर्थ मॉड्यूल को अपनाया है जिसमें से उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 26,000 से अधिक नामांकन शामिल हैं।

समर्थ पोर्टल एचईआई के लिए कैंपस भर्ती, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के लिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट मॉड्यूल प्रदान करता है। यह कंपनी पंजीकरण, नौकरी पोस्टिंग को सरल बनाता है, छात्र प्रोफ़ाइल प्रबंधन को केंद्रीकृत करता है, और नौकरी के अवसर और इंटर्नशिप तक पहुंच प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश राज्य सहित 28 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने नौकरी के अवसर प्रदान करने तथा छात्रों के लिए प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और प्लेसमेंट मॉड्यूल को शामिल किया है।

इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों की प्लेसमेंट अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रचलित बाजार परिस्थितियाँ, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आगे अध्ययन करने की विद्यार्थियों की प्राथमिकता तथा उद्यमिता एवं स्टार्ट-अप के प्रति बढ़ती रुचि प्रमुख हैं। अनेक अवर स्नातक विद्यार्थी परिसर-आधारित नियोजन (कैम्पस प्लेसमेंट) में भाग लेने के स्थान पर परिसर के बाहर स्वयं साक्षात्कारों में सम्मिलित होना अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना पसंद करते हैं।

पीएलएफएस की रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2017 में 6.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2025 में 3.1 प्रतिशत रह गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

https://www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports1780040415321_0624fb13-fb47-40bc-b470-7c7e9635c3ef_PLFS_2025_F_REV_29052026.pdf